

साप्ताहिक समाचार पत्र

त्रिकाल दृष्टि

सच का दर्पण

www.trikaldrishti.com

वर्ष-06

अंक-50,

भोपाल, सोमवार, 03 जनवरी 2022

पृष्ठ- 8

मूल्य : 3.00 रुपये

संक्षिप्त समाचार

नववर्ष में समर्थ, समृद्ध, सशक्त राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें: राज्यपाल श्री पटेल
भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुराई पटेल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि नववर्ष सभी के लिए सुख, शांति, सङ्घाव समृद्धि एवं सफलताओं का वर्ष हो। उन्होंने प्रदेश की सुख, समृद्धि की कामना करते हुए नागरिकों से सशक्त, समर्थ और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की अपील की है। राज्यपाल श्री पटेल ने नववर्ष के शुभकामना संलेख में कहा है कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नववर्ष का स्वागत स्वच्छ, स्वावलंबी, समर्थ, समृद्ध नवराष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ करें। प्रदेश के गारीब, पहुँचिलैन खेतों, गरीब और वर्षित गर्म के जीवन में खुशहाली के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रयासों में सहयोग करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी नव वर्ष की बधाई
भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नव वर्ष 2022 के आगमन की सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नव वर्ष में सभी के सुखी और समृद्ध होने की कामना करते हुए कहा कि कोरोना जैसे संकट को दूर करने में हम सब मिलकर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में सहभागी बनें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नव वर्ष पर कार्यक्रमों में कोरोना से बचाव की पूरी सावधानियों के साथ समर्पित होने का आहारन किया है।

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने श्री शैलम मलिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किये
भोपाल। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को आध्यप्रदेश के कुर्नूल जिले में श्री शैलम मलिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पूजा-अर्घ्या की। डॉ. मिश्रा ने नव वर्ष 2022 में प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की पार्थना की। मलिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कृष्णा नदी के तट पर पवित्र शैल पर्वत पर स्थित है।

वित मंत्री श्री देवड़ा ने प्रदेशवासियों को दी नव वर्ष की शुभकामनाएँ

भोपाल। वित मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि नव वर्ष सभी के जीवन में सुख-समृद्धि के साथ नई ऊर्जा का संचार करें।

खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने दी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएँ
भोपाल। खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोदा राजे सिंधिया ने प्रदेशवासियों को नूतन वर्ष 2022 की बधाई एवं शुभकामनाएँ दी है। उन्होंने कहा कि नव वर्ष सभी के जीवन में सुख-समृद्धि के साथ नई ऊर्जा का संचार करेगा। मंत्री श्रीमती सिंधिया ने प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि पिछले दो वर्षों से जारी कोरोना की जास्ती से इस वर्ष हम मुक्त हों। इसके लिए सभी लोग कोरोना गाइड-लाइन का पालन करें।

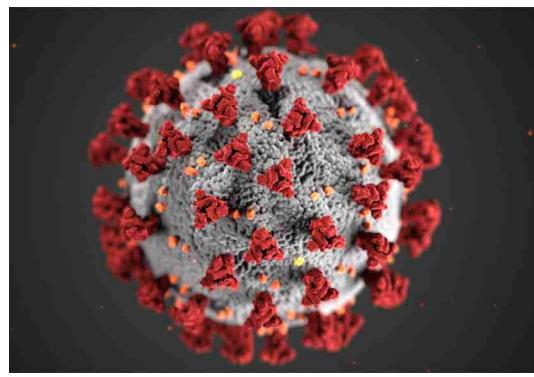
दिल्ली में डराने लगा कोरोना! एक दिन में मिले 1700 से ज्यादा पॉजिटिव, ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज बढ़े

नई दिल्ली। दिल्ली में ओमिक्रोन के बाद से कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। शुक्रवार को कोरोना के 1700 से अधिक नए मरीज मिले। मई महीने के बाद कोरोना के इन्हें मामले एक दिन में सामने आए हैं। कोरोना मामलों में बढ़ोत्तरी के चलते संक्रमण दर दो फीसदी को पार कर गई है। हालांकि ग्रहण की बात यह रही कि मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। वहाँ ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीजों की संख्या भी धीरे-धीरे बढ़ रही है।

सक्रिय मरीजों का आंकड़ा चार हजार
के पार : कोरोना के मामलों में वृद्धि होने से दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जून महीने के बाद दिल्ली में कोरोना सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4410 को छू गया है।

तेजी से बढ़ रही संक्रमण दर : कोरोना जांच बढ़ने के साथ संक्रमण दर में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी कोविड-19 स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 73590 लोगों की जांच की गई। जिसमें आरटीपीसीआर से 62812 और रैफिड एंटीजन टेस्ट से 10778 लोगों की जांच हुई। कोरोना संक्रमण की जांच दर 2.44 फीसदी दर्ज की गई। कोरोना को लेकर अब तक 32724935 सैंपल की जांच हो चुकी है।

ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज बढ़े : शुक्रवार को ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीजों की संख्या बढ़कर 82 हो गई। साथ ही वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों की



संख्या में भी इजाफा हुआ। वेंटिलेटर पर तीन मरीज गंभीर हालत में उपचार के लिए भर्ती हैं। जबकि 101 मरीजों में हल्के व कोई लक्षण नहीं हैं। अस्पतालों में कुल 226 मरीज उपचार के लिए भर्ती हैं। साथ ही 40 कोविड सर्विंग्ड, 27 एयरपोर्ट से आने वाले कोरोना संक्रमित हैं। दिल्ली के मरीजों की संख्या 135 और बाहर के मरीजों की संख्या 24 है।

होम आइसोलेशन में 2284 मरीज : होम आइसोलेशन में कोरोना के 2284 मरीजों का उपचार जारी है। जबकि अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए 226 मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर में 146 और कोविड हेल्पसेंटर में एक भी मरीज नहीं है।

कंटेनमेंट जोन की संख्या हुई 914 : अलग-अलग अस्पतालों में 8717 बेड खाली हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 914 हो गई है। कोरोना के कुल 1448211 मामले सामने आ चुके हैं। जिसमें 1418694 मरीजों ने कोरोना को मात दी और कुल संक्रमण दर 4.43 फीसदी है। साथ ही 25107 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। दिल्ली में कुल मृत्यु दर 1.73 फीसदी है। डेढ़ लाख से अधिक का टीकाकरण : बीते 24 घंटे में 170595 लोगों का टीकाकरण किया गया। जिसमें पहली डोज लेने वाले लोगों की संख्या 72639 और दूसरी डोज लालों की संख्या 97956 रही। दिल्ली में अब तक 26240608 वैक्सीन की डोज लग चुकी है।

वैष्णो देवी धाम में मची भगदड़, अभी तक 12 श्रद्धालुओं की मौत, 20 घायल

जम्मू-कश्मीरी। नए साल का पहला दिन माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गए 12 श्रद्धालुओं के लिए काल बनकर आया। देश-दुनिया जब नए साल के ज२८ ने झूँझी थी उसी दैरान कठीब सवा दो बजे माता वैष्णो देवी धाम में भगदड़ की दर्दनाक घटना हुई। इसमें अभी तक मिली आधिकारिक जानकारी में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 20 श्रद्धालु घायल बाटा जा रहे हैं। यह भगदड़ वर्षों मधीं, इसकी द्वारा आधिकारिक संसद ने अस्पताल में अभी तक 12 लोगों की मौत बताई जा रही है। यह भगदड़ जारी की जानकारी नहीं मिल पाई है। राहत और बचाव कार्य की जारी है।

घायलों को अस्पताल में भर्ती की जानकारी दी जा रही है। यह भगदड़ वर्षों मधीं, इसकी द्वारा आधिकारिक संसद ने अस्पताल में अभी तक 12 लोगों की मौत हो गई घटना लगभग 24-45 बजे हुई। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद लोगों ने एक-दूसरे को धक्का दिया, जिसके बाद भगदड़ मध्य गई।

इस हाटसे पर पीएम नरेंद्र मोदी और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल नरोज लिंग ने दुख जताया है। एलजी मनोज सिन्हा ने मरने वालों के परिवार वालों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। डॉ. गोपाल तत, प्रथम चिकित्या अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुताबिक माता वैष्णो देवी भवन में मधीं भगदड़ में अभी तक 12 लोगों की मौत बताई जा रही है। घायलों को नायायिक अस्पताल ले जाया जाया गया है।

बहस से शुरू हुई भगदड़ की शुरुआत : जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एनआई को बताया कि कटरा के माता वैष्णो देवी भवन में मधीं भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई घटना लगभग 24-45 बजे हुई। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद लोगों ने एक-दूसरे को धक्का दिया, जिसके बाद भगदड़ मध्य गई।

मेरठ में मोदी पीएम बोले-पहले यहाँ अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे

मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को 700 कब्जे की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगत दी। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इससे पहले, पीएम ने यहाँ अधिकारी की आशाधना करने के बाद शहीदों को नमन किया। इसके बाद वह सलाला के लिए दराना हुए थे। पीएम ने खेल विश्वविद्यालय की नीव द्वारा से पहले खिलाड़ियों से संवाद किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दैरान सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद गोरी, राज्यपाल आनंदीबीन पटेल, केंद्रीय पशुधन राज्यपाली संसाध बालियान भी जौगन दे रहे थे। मोदीपुरान की मेरठ वन कॉलोनी में पूर्व जिला पर्वतारत सदस्य सुनीता कुम्हेड़ी और उनके पति योगेन्द्र कुम्हेड़ी को घर पर ही पल्लवपुरान पुलिस ने नजर बढ़ कर दिया। सुनीता कुम्हेड़ी का जिला पर्वतारत अध्याधीक्षक गौरव चौहानी से पैसे के लेनदेन का विवाद चल रहा था, जिसका समझौता दो दिन पहले भाजपा विधायक जितेंद्र सतवर्द्धन के द्वारा किया गया था।

कालीचरण महाराज गिरपतार गांधी पर की थी अमर्यादित टिप्पणी

रायपुर। बाला गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराजको मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरपतार कर लिया गया है। यह गिरपतारी छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने की है। कालीचरण पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई जगह गुकड़े दर्ज किए गए थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जहाँ एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने गहाता गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिखा पत्र

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आवास मिलने पर उनके नाम निजी पत्र लिखकर उन्हें बहुत-बहुत बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 'मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि आप अपने नवीन आवास में हर्ष एवं आनंद के साथ निवास कर रहे होंगे। योजना में आपका चयन हुआ तथा आपके द्वारा आवास निर्माण पूर्ण किया गया, इसके लिये आपको बधाई। आपके और आपके परिवार के लिये समृद्धि की कामना करते हुए हार्दिक शुभकामनाएँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि आवास प्रत्येक परिवार की मूलभूत आवश्यकता है। इसी अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए सबके लिये आवास-2022 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) प्रारंभ की गई है। योजना में गरीब परिवारों के सर्वांगीन विकास के लिये आवास निर्माण के लिये एक लाख 20 हजार रुपये/ एक लाख 30 हजार रुपये, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिये प्रत्रता अनुसार 12 हजार रुपये और मनरेगा से 18 हजार रुपये की

सहायता राशि के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी परिवार को दिया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि आवासविहीन गरीब परिवारों के लिये घर बह उपहार है, जिससे न केवल उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अपितु उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आवास युक्त परिवार गरीबी के बंधन से मुक्त होकर जीवन में सफलता के मार्ग पर बढ़ने में सक्षम हो जाता है तथा बच्चों की पढ़ाई तथा उनके सफल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

स्वैच्छिक पुनर्स्थापन स्वीकार करने वाले प्रत्येक परिवार को अब 10 लाख की जगह 15 लाख का मुआवजा: वन मंत्री डॉ. शाह

भोपाल। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों और टाईगर रिजर्वस कॉरीडोर क्षेत्र के ग्राम से स्वैच्छिक पुनर्स्थापन स्वीकार करने वाले परिवार इकाइयों को प्रति परिवार अब 15 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने राज्य शासन द्वारा लिए

गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया है कि इसके पहले वर्ष 2008 से संरक्षित ग्रामों से विस्थापन के लिए मुआवजा राशि प्रति परिवार इकाई 10 लाख रुपए दी जाती थी। वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि 13 साल की इस अवधि में समय के साथ इस राशि को पर्यास न मानकर राज्य ने विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक मंचों से इसे बढ़ाने के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया। प्रस्ताव पर भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय व्याप्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली ने प्रस्तावित मुआवजा राशि को अपनी मंजूरी दे दी। वन मंत्री ने बताया कि मंत्रि-परिषद की 7 दिसम्बर 2021 को हुई बैठक में पुनर्वास के लिए मुआवजा पैकेज में बढ़ातरी सहित योजना क्र. 5109 की निरंतरता को अनुमोदित किया गया। 300 करोड़ रुपए का प्रावधान वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि वर्ष 2022-23 में पुनर्स्थापन के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसमें कैम्पा मद से 285 करोड़ और योजना क्रमांक 5109 में पुनर्स्थापन के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्टार्ट पार्क और हमीदिया अस्पताल परिसर में गौलश्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्यामला लिल्स रिटेल स्टार्ट पार्क में गौलश्री और पीपल का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ कुंजल वेलफेयर सोसायटी के सदस्य श्री आर.एन. पाटिल, श्रीमती प्रमा गौर, श्री ईश्वर कुमार, सुश्री कुंजल, सुश्री प्रियल ने भी पौध-रोपण किया और संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। संस्था द्वारा प्रदेश में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत पाँच हजार से अधिक महिलाओं को पेपर बैग, लिफाफे, फाइल फोल्डर तैयार करने का हुनर दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान को कुछ उत्पादों के नमूने भी मैट किए गए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हमीदिया अस्पताल के निरीक्षण के दौरान भी अस्पताल परिसर में सप्तपर्णी का पौधा

लगाया। पौधों का महत्व : गौलश्री को संकृत में केसव, हिन्दी में गौलसरी या बकूल भी कहा जाता है। यह एक औषधीय वृक्ष है, जिसका सदियों से आयुर्वेद में उपयोग होता आ रहा है। पीपल एक छायादार वृक्ष है। यह पर्यावरण शुद्ध करता है। इसका धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व है। प्रकृति विज्ञान के अनुसार पीपल का वृक्ष दिन-रात दोनों समय अँकसीजन छोड़ता है, जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीपल के पेड़ को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ कभी भी पते विहीन नहीं होता। सप्तपर्णी का पौधा एक सदाबहार औषधीय वृक्ष है, जिसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इस औषधीय पौधे का उपयोग विभिन्न दवाओं के निर्माण में किया जाता है।

शासकीय सेवा में फर्जी नियुक्ति के आरोपियों के विट्टु वार्ड कार्टवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश लोकायुक्त के संज्ञान में आने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार और फर्जी नियुक्ति के आरोपी 119 व्यक्ति में से 35 व्यक्ति को जाँच के बाद शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिये गये वेतन-भत्तों की शाशि की वसूली की जा रही है। फर्जी नियुक्ति के आरोपी शेष व्यक्तियों के विट्टु अनुशासनात्मक कार्टवाई जारी है। आरोपी और सलिल अधिकारियों-कर्मचारियों के विट्टु सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही भी की जा रही है। सर्वदलीय संघर्ष समिति दिया ने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य योजनाओं में अटावार और फर्जी नियुक्तियों के संबंध में मध्यप्रदेश लोकायुक्त से शिकायत की थी। लोकायुक्त ने

प्रकरण पंजीबद्ध कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से विस्तृत प्रातिवेदन प्राप्त किया। प्रारंभिक जाँच में ज्ञात हुआ कि आरोपियों ने स्वास्थ्य संचालनालय से फर्जी आटेंज जारी कराकर और जिला कोषालय दिया से फर्जी यूनिक कोड बनवाकर शासकीय सेवा में अवैध नियुक्ति प्राप्त की। आरोपियों ने शासन को करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुँचाया है। आरोपियों को वेतन-भत्ते में एक करोड़ 67 लाख 18 हजार 850 रुपयों का भुगतान हुआ है। आरोपियों में से कुछ कर्मचारियों के विट्टु प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। वर्तमान में इस प्रकरण में स्वास्थ्य संचालनालय स्तर पर गतिरोध नियमित द्वारा विनाकित 119 आरोपी व्यक्ति में से 13 आरोपी को जाँच प्रिपोर्ट के आधार पर जिला दिया के मुद्द्य पिक्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

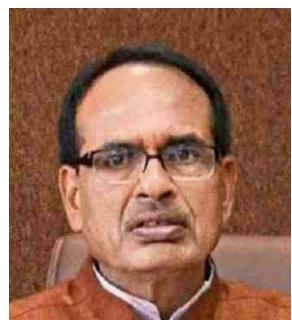
खबरें

वैरिएंट स्वरूप न बदले, हम सब रहें सजग : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि देश में इस वैरिएंट ने दस्तक दी। हर राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित नागरिकों की संख्या सामने आ रही है। मध्यप्रदेश में भी 77 प्रकरण पॉजिटिव आए हैं। इनमें सर्वाधिक इंदौर में हैं। हम समय रहते सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं ताकि हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। साथ ही यह भी जरूरी है कि आमजन सभी सावधानियों का पालन कर सजग रहें। फेस मॉस्क के उपयोग, परस्पर दूरी जैसी सावधानियों का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस समय प्रदेश में विभिन्न शासकीय और निजी अस्पतालों में करीब 60 हजार ?बिस्टर क्षमता उपलब्ध है। कोविड केरायर सेंटर भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज भोपाल के हमीदिया अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करने के बाद प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए संकल्पबद्ध है।

आवश्यकता के अनुसार हो ऑक्सीजन उपयोग : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन कर आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। ऑक्सीजन के उपयोग का ऑडिट भी अब किया जाएगा ताकि अनावश्यक ऑक्सीजन की खपत न हो। आम जनता के साथ मिलकर पूरी ताकत से ओमिक्रॉन का मुकाबला किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल के निरीक्षण के साथ ही पूरे प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य और उपचार सुविधाओं के लिए वे स्वयं निरंतर समीक्षा कर रहे हैं, यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। वैरिएंट स्वरूप न बदले, हम सब रहें सजग : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाओं के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। पर्यास औषधियों की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। संक्रमण की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। वैरिएंट के स्वरूप बदलने की आशंका को ध्यान में रखकर गोपी संख्या बढ़ने और



उनके उपचार के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं। हम सभी को सजग बने रहना है।

डॉक्टर्स और स्टाफ से किया आव्हान : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का आव्हान किया कि वे एक बार फिर कर्तृत्व निर्वहन के लिए तपतर रहें। यह परीक्षा की घड़ी है, हम सभी को मिलकर जनता को संकट से बाहर सुरक्षित ढंग से निकालकर लाना है।

वैक्सीनेशन कार्य को मिली है गति : मुख्यमंत्री

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश वैक्सीनेशन के कार्य में गतिशील है। प्रदेश के करीब सब पाँच करोड़ लोगों को प्रथम और करीब पाँच करोड़ लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज़ लग चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाकर सभी के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की है। अब 15 से 18 वर्ष के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के रोगग्रस्त नागरिकों को टीका लगाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के विद्यालयों में बच्चों के लिए टीकाकरण क

नए साल में उम्मीद जगाती खबर: यातायात और अपराधों पर नियंत्रण के लिए पूरे शहर में लगेंगे कैमरे

इंदौर। यातायात समस्या और अपराधों पर अंकुश के लिए नए साल में उम्मीद जगाती खबर सामने आई है। इसके लिए नगर निगम के माध्यम से एक एकीकृत व्यवस्था इंटीग्रेटेड सिस्टम विकसित की जाएगी। इसके तहत पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और घरों के बाहर लगाए गए निजी कैमरों की निगरानी भी इस सिस्टम के जरिए होगी। इसके लिए शासन स्तर पर कानून (बायलाज) बनाया जा रहा है। कानून बनने के बाद इंदौर में इस तरह की एकीकृत व्यवस्था पर अमल शुरू हो जाएगा। घरों में लगे उन्हीं कैमरों को इसमें शामिल किया जाएगा जिनका फोकस बाहर की तरफ हो।

कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक, संभावना है कि इस व्यवस्था के लिए चार-पांच महीने में शासन की मंजूरी मिल जाएगी। तब हम इसी साल एकीकृत व्यवस्था पर काम शुरू कर देंगे। दरअसल, यह सब शहरी परिवहन का हिस्सा है, इसलिए मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम के तहत इसके नियम बनाए जाएंगे। इस एकीकृत माडल के जरिए हम यातायात पर तो नियंत्रण

रखेंगे ही, नगर निगम के रखरखाव के कार्यों की भी निगरानी कर सकेंगे। इस व्यवस्था से अपराधियों को भी पकड़ा जा सकेगा। जो लोग अपराध करके गाड़ी से भाग रहे होंगे, उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी यह कैमरे पढ़ सकेंगे। इसके जरिए उनको पकड़ने में मदद मिलेगी। यातायात के नियम तोड़ने वालों के घर आटोमेटिक चालान पहुंचेंगे। उनकी तामीली की जाएगी। जो लोग नियम तोड़ने की गलती करेंगे, उनको दंडित किया जाएगा। इस एकीकृत व्यवस्था का कंट्रोल कमांड सेंटर सिटी बस कार्यालय में रहेगा। शहर के सारे कैमरे इस सिस्टम से जुड़े रहेंगे।

प्रसूताओं को प्राइवेट अस्पताल मेजने वालों पर हो कार्रवाई

उज्जैन। शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख थकवार को बृहस्पति भवन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। कलेक्टर आर्योदीप सिंह ने बताया कि अमजन को गार्फ पहनने के लिए योंको टोको अग्नियान घलाया जाएगा। प्रमुख घौराहों पर कोरोना से बचाव के लिए मास्टर पहनने और दो गज की शारीरिक दूरी बनाए रखने की उद्देश्या की जाएगी। इसी बीच सांसद ने एक अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं को प्राइवेट अस्पताल रेफर किए जाने का जिक्र किया।

हीरक जयंती पर दिखी एकजुटता की चमक

उज्जैन। बैता समाज द्वारा शुक्रवार को समाज का 75 वां स्थापना दिवस हीरक जयंती के रूप में मनाया गया। सुबह बागपुरा स्थित संत बालीनाथजी के मटिर से विशाल वाहन ऐली निकाली गई। संत महाल्मातों के सानिध्य में निकली ऐली में समाज एकजुट नजर आया। प्रमुख मार्ग से होते हुए ऐली किशनपुरा पहुंचकर संपन्नः हुई। शाम 7 बजे तीन बर्ती स्थित संत बालीनाथ घौराह का नामकरण एलईडी लाइट के माध्यम से समाजगनों की मौजूदगी में किया गया। आनंदक मनोज लोदवाल व रुजेश जारवाल ने बताया सुबह बागपुरा स्थित संत बालीनाथ मदिर से उच्चशिख मंत्री डा. मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक मधेश परमार आदि ने संत बालीनाथजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ऐली का शुभारंभ किया। इसके बाद समाजगन संत बालीनाथजी की प्रतिमा तथा विशाल ध्वनि लेकर

भ्रमण के लिए रवाना हुए। ऐली में सबसे आगे समाज के सभी संत महाल्मा रथ पर विरजामान होकर समाज की एकता व अंकुशता के साथ हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते चल रहे थे। सैकड़ों दोपहिया, चार पहिया व मैनिक वाहनों में युवा साथी सवार होकर निकले। बैठ, बाजे, डीजे वाहन पर संत बालीनाथजी के भजनों की धून पर बैता समाज के लोग भक्ति में झूमते चल रहे थे। चल समारोह का अनेक स्थानों पर पृष्ठ तर्फ स्वागत किया गया। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ऐली किशनपुरा पहुंचकर संपन्नः हुई। चल समारोह में प्रमुख रूप से मदनलाल ललावत, माधो प्रसाद शासी, नीना जोनवाल, दीपक मेहरे, सुरेंद्र मरमट, जितेंद्र तिलकर, लालचंद भारती, आनंद बागेश्वर, अंगु जाटवा, सुनील गोवाल, जगदीश मरमट, दीनदयाल बड़ेदिया, राजकुमार खालीपाण सहित सैकड़े समाजगन शामिल थे।

आधी दात को कार दोकी तो युवकों ने नशे में पुलिसकर्मियों से मारपीट कर वर्दी फाड़ी

उज्जैन। यात्री दात के दौरान गुरुवार रात को भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े युवकों की कार दोकाने पर घर लोगों ने मिलकर माधव नगर थाने में पदस्थ एसआइ के साथ मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ दी। साथी पुलिसकर्मियों ने जब पुलिस कंट्रोल रूम को बायलेस पर काल कर पुलिस बल बुलाया तो दो युवक स्कार्पियों गाड़ी से तथा दो युवक कार से भाग निकले। स्कार्पियों गाड़ी को नानारेड़ा पुलिस ने कासमास माल के समीप दोका तो वाहन में सवार दो युवकों ने एक एसआइ के साथ मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ दी। वही दूसरी कार को नीलगंगा पुलिस ने हरिकाटक पुल पर दोका लिया। उस दौरान एक युवक कार से उतरकर भाग निकला। माधवनगर व नानारेड़ा पुलिस ने शासकीय कार्य

में बाग व मारपीट के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। कोर्ट ने दो आरोपितों को जेल मेजने के आदेश जारी कर दिया। माधवनगर पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात को थाने में पदस्थ एसआइ महेंद्र मकाश्रे सेक्टर अधिकारी तथा एसआइ प्रेम मालवीय गश्त अधिकारी के रूप में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान दशहरा मैदान स्थित सुराना होटल के सभी प्राथ्या गर्डन के बाहर एक काले रंग की कार में कुछ युवक बैठे हुए थे। इस पर एसआइ मालवीय और मकाश्रे ने कार में सवार युवकों से पूछताह की थी कि वह इतनी रात को तयों घूम रहे हैं। चारों युवकों ने खुद को भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा होना बताया तथा पुलिसकर्मियों के साथ नशे में अभद्रता शुरू कर दी।

उसे कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उसे दो दिन के पुलिस दिमांड पर सौंप दिया गया।

नव वर्ष 2022 और इंदौर : खत्म हो रहे पेड़, 21 प्रतिशत हरियाली बढ़ानी थी

इंदौर। मास्टर प्लान के अनुसार इंदौर का एक तिहाई क्षेत्र हरित होना चाहिए, जबकि हकीकत काफी अलग है। हरियाली बढ़ाने के नाम पर नगर निगम और आईडीए उद्यान व हरित क्षेत्र विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद पौधों की संख्या नहीं बढ़ रही है। उद्यानों के विकास के नाम पर वहां पौधारोपण के बजाय कांक्रीट के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। शहर में सड़क चौड़ीकरण व भवन निर्माण में हर साल सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरणविद ओपी जोशी के मुताबिक मास्टर प्लान के तहत इंदौर में विगत एक साल में 21 प्रतिशत हरित क्षेत्र बढ़ाया जाना था, लेकिन सिर्फ सात से दस प्रतिशत ही बढ़ा है। निगम, आईडीए जैसी एजेंसी हरियाली की योजनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। पौधारोपण के बजाय पुराने पेड़ों को बचाने की जरूरत है। जनवरी से दिसंबर तक इंदौर में 32 स्थानों पर 200 पेड़ काटे जाएं। इसके अलावा 44 स्थानों के पेड़ गिरे। इस तरह एक साल में करीब 275 पेड़ों को नुकसान हुआ है। खंडवा रोड चौड़ीकरण के लिए भी 400 और कैट रोड चौड़ीकरण के लिए 200 पेड़ों को काटने की तैयारी है। सड़क निर्माण के लिए पेड़ों का ट्रांसप्लांट भी पूरी तरह नहीं हो पा रहा है।

पौधे लगाए। अब रिंग रोड के ग्रीन बेल्ट को अतिक्रमणमुक्त कर हरियाली बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कई अवैध कालोनियों में ग्रीन बेल्ट व बगीचे की जमीन नहीं छोड़ी गई। वैध कालोनियों में कई स्थानों पर हरित क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है।

हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए खोजनी पड़ेगी जमीन : पिछले पांच वर्षों में सिरपुर में बफर जोन बनाकर 12 हजार पौधे लगाए गए हैं। पिन्हे पर्वत पर 16 वर्षों में लोगों ने पितरों की स्मृति में 65 हजार पौधे रोपे हैं। निगम ने चार साल में 60 हजार पौधे लगाए हैं। ट्रैकिंग ग्राउंड और बिलावली तालाब की पाल पर पौधे लगाए गए हैं। शहर में हरित क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। इस वजह से मास्टर प्लान में हरियाली के तय आंकड़े को हम छू नहीं पाए हैं। हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए जमीन खोजनी पड़ेगी। निगम की नर्सरी में करीब तीन लाख पौधे हैं, जिसमें डेढ़ लाख पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए जगह निर्माण के लिए खोजनी चाहिए।

नव वर्ष 2022 और इंदौर: पेयजल की चिंता - वर्ष 2040 तक शहर को होगी 1200 एमएलडी पानी की दरकार

इंदौर। जिस तरह इंदौर शहर की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से पेयजल की आवश्यकता भी बढ़ रही है। नगर निगम मौजूदा साढ़े 28 लाख

आबादी को नर्मदा का 450 एमएलडी पानी, यशवंत सागर से 30 एमएलडी व नलकूपों के माध्यम 20 एमएलडी पानी वितरित कर रहा है। वर्ष 2040 तक आबादी लगभग 60 लाख हो जाएगी। इसके हिसाब से 1200 एमएलडी पानी की दरकार होगी। वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति नगर निगम करता है लेकिन कई लोग इसका उपयोग बगीचों और गाड़ियों धोने में भी करते हैं। कई लोग अन्य प्रकार से बर्बाद करते हैं। सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी टायलेट फ्लश में होती है।

हरियाली के लिए उपचारित जल का उपयोग : जल प्रबंधन विशेषज्ञ सुधींद्र मोहन शर्मा के मुताबिक प्रटूषण नियंत्रण मंडल के नियमों के तहत सभी उद्योगों में दूषित जल को उपचारित करने का संयंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। यह भी अनिवार्य किया गया है कि उद्योग उपचारित जल का उपयोग अपने परिसर के बगीचों और शौचालयों में करें। बायपास स्थित कई बड़ी टाउनशिप में उपचारित पानी का उपयोग बगीचों में किया जाता है। बांबे अस्पताल में 50 हजार लीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग बगीचों की हरियाली में किया जाता है। उद्यानों और निर्माण कार्यों में 101 एमएलडी उपचारित पानी का उपयोग : ट्रैटमेंट प्लांट के जरिये नगर निगम सीवरेज को उपचारित कर रहा है। उपचारित पानी

का उपयोग निगम के उद्यानों में किया जा रहा है। निर्माण कार्यों के लिए भी इसे दिया जा रहा है। सांवर तहसील के पांच गांवों के किसानों को यह उपचारित पानी दिया जा रहा है। निगम ने विजय नगर क्षेत्र में टंकी बनाई है, जिसके माध्यम 13 एमएलडी पानी प्रतिदिन उद्यानों को दिया जाता है। निगम छह उपचारित पांच गांवों के हाइड्रेंड से पानी वितरित कर रहा है। कबीटखेड़ी में 245 एमएलडी वाला सीवरेज ट्रैटमेंट प्लांट 32 हाइड्रेंड के जरिये जल वितरण करता है।

संपादकीय

कठिन हालात में दी कोरोना को मात

23 मार्च 2020 – यही वह दिन था जब शिवराज सिंह चौहान पुनः मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पर इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं थी। प्रदेश में जहाँ एक ओर कोरोना ने पांच पसारे हुए थे, वहाँ अर्थिक स्थिति रसातल में पहुंच चुकी थी। शिवराज की स्थिति रणभूमि में खड़े उस कर्मचार योद्धा की तरह थी, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था और सामने प्रबल सत्रु लड़ने के लिए तैयार था। ऐसी स्थिति किसी भी जनसेवक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। पर शिवराज कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। तीन बार मुख्यमंत्री पद के अनुभव के साथ लंबा राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभव उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जनता की सेवा का उनका जज्बा अतुलनीय है। वह प्रदेश को अपना मंदिर, जनता को भगवान और स्वयं को उसका पुजारी समझते हैं। शिवराज ने कमर कस ली और 100 दिन की अल्पावधि में ही न केवल कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया बल्कि ध्वस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में भी नए प्राणों का संचार कर दिया। कार्यभार ग्रहण करते ही शिवराज ने रात में ही मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली। उन्हें यह भान तो था ही कि प्रदेश की स्थिति विकट है, परंतु यह अंदाजा बिल्कुल भी न था कि कोरोना से निपटने के लिए व्यवस्थाएं शून्य हैं। चकाचौंध के पीछे की स्थानीय कोशिश की प्रभावी रणनीति बनाकर इस पर तेजी से अमल शुरू किया।

कर्जमाफी के लुभावने वालों, आईफा जैसे आकर्षक आयोजनों से कुछ दिन तो दिल बहलाया जा सकता था, परंतु धरातल पर यह कितने दिन टिकते? एक ओर जहाँ प्रदेश के कुछ बड़े नगरों में कोरोना अपना असर दिखा रहा था, वहाँ दूसरी ओर उससे लड़ने के लिए कोई इंतजामात नहीं थे। प्रदेश में मात्र एक लैब था जिसकी 60 टैस्ट प्रतिदिन क्षमता थी। कोविड अस्पताल तैयार नहीं थे और न मास्क, पीपीई किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटीलेटर्स की ही व्यवस्था थी। संक्रमण की स्थिति में जल्दी से जल्दी सारी व्यवस्थाएं करना 'हरकुलियन टास्क' था।

शिवराज सिंह ने अधिकारियों, प्रबुद्धजनों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया आदि सभी से विचार-विमर्श कर कोरोना पर नियंत्रण की प्रभावी रणनीति बनाकर इस पर तेजी से अमल शुरू किया। आई.आई.टी.टी. अर्थात् 'आईडेंटीफाई, आयसोलेट, टैस्ट एण्ड ट्रीटमेंट' की रणनीति बनाई गई। हर जिले में डेंडिकेटेड कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर चिन्हित किए गए। साथ ही, निजी अस्पतालों को भी अनुबंधित किया गया। अस्पतालों में आयसोलेशन बैड्स, ऑक्सीजन, वेंटीलेटर्स, हाइड्रोक्सीलोरीक्लीन सहित अन्य दवाएं, मास्क, पीपीई किट आदि सभी आवश्यक सामग्रियां तो जुटाई ही गईं, साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों का समूह बनाकर कोरोना के इलाज की पुख्ता व्यवस्था की गई। दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धोषित लॉकडाउन को प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया गया। पहली चुनौती थी टैस्टिंग क्षमता को जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाना, जिससे कि एक-एक मरीज की पहचान कर उन्हें आयसोलेट कर इलाज किया जा सके तथा संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सभी मैडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में टैस्टिंग लैब बनाए गए तथा टैस्टिंग क्षमता को तेजी से बढ़ाया गया। इसके अलावा हवाई जहाज से कोरोना के सैम्प्ल दिल्ली तथा अन्य महानगरों को भिजवाए गए, जिससे कि तेजी से जाँच की जा सके। आज की स्थिति में प्रदेश की टैस्टिंग क्षमता लगभग दस गुना बढ़कर 6000 से अधिक हो गई है। दूसरी बड़ी समस्या थी पीपीई किट की अन-उपलब्धता जिसके अभाव में हमारे कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी आदि को संक्रमण का खतरा था। इसके लिए व्यापक पैमाने पर प्रयास किए गए तथा जल्द ही मध्यप्रदेश में बनाया गया पीपीई किट गुणवत्ता पर खरा उत्तरा। हर कोरोना योद्धा को पीपीई किट उपलब्ध कराए गए। कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा कवच देने के लिए सरकार ने 50 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान किया है। उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रतिदिन हर जिले की बीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते रहे। इसके साथ ही चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ रोज इलाज की स्थिति जानते रहे। प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर कम करने के लिए 'डेंथ ऑडिट' प्रारंभ किया गया। एक-एक प्रकरण की समीक्षा की गई। थोड़ी भी लापरवाही पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई तथा इलाज की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिसके चलते प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट तेजी गति से बढ़ी। आज मध्यप्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 76.9 प्रतिशत है।

सर्वश्रेष्ठ उपचार के साथ ही संक्रमण को रोकना बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसमें मध्यप्रदेश अत्यधिक सफल रहा है। लॉकडाउन के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही गहन सर्वे, आयसोलेशन, होम क्रारेंटाइन, सुरक्षात्मक उपायों के उपयोग के लिए जनसामान्य को जागरूक करना, निरंतर जनता से अपील करना, समाज के सभी वर्गों का सहयोग लेना, कोरोना के संक्रमण को रोकने में मददगार साबित हुए। हर जिले में 'क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप' के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां संचालित करना आदि वे कदम थे जिनसे मध्यप्रदेश में कोरोना के संक्रमण को बहुत तेजी से नियंत्रित किया गया। आज मध्यप्रदेश का कोरोना ग्रोथ रेट 1.44 रह गया है, जो भारत की कोरोना ग्रोथ रेट 3.69 से आधे से भी कम है। मध्यप्रदेश में कोरोना की डबलिंग रेट 48 दिन हो गई है। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत में 13वें स्थान पर आ गया है। वहाँ सर्वाधिक प्रकरणों की दृष्टि से मध्यप्रदेश 9वें स्थान पर आ गया है।

प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए योग एवं आयर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी आदि दवाओं के माध्यम से रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को प्रभावी हथियार के रूप में अपनाया गया। आयुष विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में 2 करोड़ से अधिक त्रिकटु काढ़े के पैकेट्स वितरित किए गए।

गरीबों के लिए पूरा पैकेज है संबल योजना

किसी भी सरकार का धर्म है कि जो गरीब है, दीन है, दुखी है, पिछड़े हैं उनको विशेष सुविधाएँ दी जाये। महात्मा गांधी लगातार कहते थे कि सरकार का पहला काम निर्धनों की सेवा है। पूज्य डॉ. हेडोवार ने कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि दरिद्र ही नारायण है, गरीब ही भगवान है, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। मध्यप्रदेश सरकार इन्हीं महापुरुषों के बताये रास्ते पर चल रही है। गरीबों के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्व में ही शुरू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना को फिर से शुरू किया गया। फिर से इसलिए शुरू किया गया क्योंकि पिछले सरकारों ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

एक नई योजना इसमें जोड़ी है, संबल परिवार के ऐसे बच्चे जो 12वें में मेरिट में आते हैं ऐसे 5 हजार बच्चों को 30 हजार रूपये प्रति विद्यार्थी अलग से दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान का कहना है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम में गरीब बच्चों का चयन हो जाता है तो फीस भरना उसके बूते की बात नहीं है, इसलिए सरकार फीस की व्यवस्था करती है। पढ़ाई के साथ ही खेल में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना शुरू की गई है, इसके अंतर्गत संबल परिवार के बच्चों जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्प्लिटेशन या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे उन्हें 50 हजार प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है।

संबल योजना में गरीबों को सस्ते दर पर बिजली तथा बीमारी के लिए सहायता भी दी जाती है। पंजीकृत व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की राशि परिवार के सहारे के लिए दी जाती है। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपये, अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रूपये की व्यवस्था संबल में की जाती है। आंशिक स्थाई अपनांगता पर भी अर्थक सहायता संबल के तहत मिलती है। संबल गरीब के लिए एक पूरा पैकेज है, ऐसी योजना देश में किसी भी राज्य में नहीं है। समाज में नीचे खड़े व्यक्ति को बराबर पर खड़े करने के लिए यह योजना एक संबल है। मार्च से 20 जून की स्थिति में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 25 हजार 171 योजना के हितग्राहियों को 151 करोड़ 13 लाख की सहायता दी है। मध्यप्रदेश देश का एकमात्र ऐसा बिला प्रदेश होगा, जहाँ गरीब वर्ग की जन्म से लेकर मृत्युतक होने वाले व्यय की जिम्मेदारी शासन उठाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान की संवेदनशील सोच से उपजी संबल योजना में यह सब कवर होता है। गरीबों के प्रति हमेशा मन में चिंता लिए श्री चौहान यह चाहते हैं कि प्रदेश का कोई भी गरीब परिवार असहाय स्थिति में किसी के आगे न गिर्दिगिर्द ये। इसलिए गरीब परिवार के घर में होने वाली प्रसूति, बच्चे का जन्म, बच्चों की पढ़ाई के साथ परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु, सामान्य मृत्यु, दुर्घटना में हुई स्थाई और अस्थाई अपनांगता के साथ अंत्येष्टि सहायता भी संबल योजना में उपलब्ध करवाई जाती है।



SAAP SOLUTION

Explore New Digital World

All Types of Website Designing

- Business Promotion,
- Lease Website
- Industrial Product Promotion through industrialproduct.in
- Get 2GB corporate mail account @ Rs 1500/- Per Annum per mail account with advance sharing feature

Logo Designing by Experts

Bulk SMS Services

For more details visit our website saapsolution.com

For enquires contact on 9425313619,

Email: info@saapsolution.com



ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को डिप्रेशन होने का खतरा

कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किए गए एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बड़े बच्चों में अवसाद और अति व्यग्रता बढ़ने का खतरा बहुत बढ़ गया।

कनाडा में महामारी के दौरान 2000 से अधिक स्कूली छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के विश्लेषण से यह बात सामने आई है। यह रिपोर्ट इन छात्रों के अभिभावकों ने ही उपलब्ध कराई थी। टोरंटो स्थित 'हॉस्पिटल फॉर सिक चिल्ड्रेन' के विशेषज्ञों ने इस अध्ययन में विभिन्न प्रकार के स्क्रीन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध होने का भी खुलासा किया।

उन्होंने पाया कि बड़ी उम्र के छात्रों में अभिभावकों द्वारा दी गई रिपोर्ट और अवसाद एवं व्यग्रता बढ़ने के बीच स्पष्ट संबंध है। टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, 'इन निष्कर्षों से पता चलता है कि माहमारी के दौरान और उसके के बाद भी बच्चों और युवाओं में स्वास्थ्यप्रद स्क्रीन के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और सामाजिक समर्थन आवश्यक हो सकते हैं।' अध्ययन में शामिल वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि महामारी के दौरान छोटे बच्चों में

अधिक समय तक टीवी देखने और गेम खेलने से भी भारी मात्रा में अवसाद, व्यग्रता, व्यवहार संबंधी समस्याएं और अति सक्रियता की समस्या देखी गई। विशेषज्ञों के अनुसार, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों में इस तरह की समस्या के बढ़ने का कोई खतरा नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह समस्याएं लंबे समय तक स्क्रीन पर बैठने और सामाजिक संपर्क के लिए बहुत कम समय देने के कारण हो सकती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा, 'कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों की दिनचर्या में बड़ा बदलाव आया है।'

प्रमुख निष्कर्ष

-2026 कनाडाई बच्चों को कोविड-19 महामारी के दौरान अध्ययन में शामिल किया गया

-532 बच्चे 5.9 वर्ष औसत आयु वर्ग के टारजेटिक्स में शामिल किए गए थे!



-1494 बच्चों को तीन अन्य समूहों में शामिल किया गया जिनकी औसत आयु 11.3 वर्ष थी।

-237 बच्चों में पहले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) हो चुका था, जिनका निदान भी हो गया था।

-टीवी या डिजिटल मीडिया में अधिक समय देनेवाले छोटे बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं अधिक देखी गईं।

-टीवी या डिजिटल मीडिया में अधिक समय देनेवाले बड़े बच्चों में गहरे अवसाद, व्यग्रता और असावधानी की समस्याएं देखी गईं।



किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस के मुकाबले ज्यादा बेहतर

हाल ही में किए गए एक शोध में दावा किया गया है कि एक बार किडनी

(गुरुदा) खराब होने के बाद दोबारा

प्रत्यारोपण डायलिसिस की तुलना में

जीवन बचाने में बेहतर होता है। यह

अध्ययन सीजेएसएन पत्रिका में प्रकाशित हुआ।

ऑस्ट्रिया में मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के प्रोफेसर रेनर ओबरबाडर के नेतृत्व में अध्ययन किया गया। जिसमें 2,346 वयस्कों को शामिल किया गया। रेनर ओबरबाडर के मुताबिक, अध्ययन में पता चला कि पहली बार गुरुदा प्रत्यारोपण असफल रहने के बाद दूसरी बार प्रत्यारोपण कराना डायलिसिस की तुलना में कारगर होता है। शोध में पाया गया कि जिन लोगों का डायलिसिस किया गया, पुनर्प्रत्यारोपण के मुकाबले उनकी मृत्यु पहले हो गई। वहीं, पुनर्प्रत्यारोपण कराने वालों की करीब छह माह बाद मृत्यु हुई।

दर्द से राहत दिलाते हैं ये नैचुरल पेनकिलर्स, इमरजेंसी के लिए हमेशा एक्योनी

हर किसी को कभी न कभी दर्द जरूर होता है। ऐसे में कुछ लोग तुरंत दवा खोजने लगते हैं वहीं कई लोग पेनकिलर्स लेने से बचते हैं। ऐसे में थोड़ा-बहुत लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं कभी-कभी ऐसा कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि दवाओं पर डिपेंड रहने से शरीर में कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप भी केमिकल वाली दवाओं से बचना चाहते हैं तो कुछ नैचुरल पेनकिलर्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे हर घर में समय-समय पर बुर्जुग ये नुस्खे बताते रहते हैं। यहां आप जान सकते हैं कि किचन की कौन सी चीज आपके किस तरह के दर्द में काम आ सकती है।

हल्दी : हल्दी के फायदे हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। घरों में इसको मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक एक्सपर्ट अपने लॉग में जिक्र कर चुके हैं शरीर दर्द या गठिया में हल्दी जादू की तरह काम करती है। अगर आपके चोट हैं और त्वचा छिल गई है या नीला पड़ गया है तो वहां भी सरसों के तेल में हल्दी, लहसुन गरम करके लगाने से आराम मिलता है।

लहसुन: लहसुन में वायरस, बैक्टीरिया और फंगस मारने वाले गुण होते हैं। कूफा मेडिकल जरनल की स्टडी के मुताबिक, कान दर्द में लहसुन से काफी फायदा होता है। इसके लिए लहसुन का तेल इस्तेमाल किया जाता है।

पेपरमिंट: अगर आपकी मसल्स में दर्द है तो पेपरमिंट काफी फायदा करता है। सिररद्द में भी कई लोग पेपरमिंट का तेल लगाते हैं।

आयुर्वेद व होमियोपैथी के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा घर बैठे पाये उचित परामर्श व दवाईयां



आयुष समाधान

- सभी रोगों का अनुभवी डॉक्टरों द्वारा होमियोपैथी व आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाता है।
- रुपये 500/- से अधिक की दवाईयों पर निःशुल्क डिलेवरी
- किसी भी प्रकार की एलर्जी का इलाज किया जाता है।
- यौन रोगियों का सम्पूर्ण इलाज किया जाता है।
- रजिस्टर्ड डायटीशियन से वजन कम करने हेतु व अपने सही डाईट प्लान हेतु सम्पर्क करें

Email: info@ayushsamadhaan.com

www.ayushsamadhaan.com

FOR MORE DETAILS & BENIFITS VISIT OUR WEBSITE FOR REGISTRATION

लॉ से खुलेगा कैरियर, कॉन्सेप्ट समझकर करें तैयारी- क्लैट 2018 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

सफल जीवन जीने के लिए एक अच्छे सलाहकार की जरूरत होती है। इसके लिए कानून के जानकार का होना बेहद जरूरी होता है। परीक्षा के लिए आपका बेसिक फंड मेंटल क्लीयर होना बहुत जरूरी है। अगर आप भारतीय संविधान को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो यह आपके हित में होगा। पूरी तैयारी के बाद कोशिश करें कि इससे पहले के सभी पेपरों को आप खुद सॉल्व करें। किसी भी जानकारी को रटें नहीं, बल्कि हर टॉपिक को सिर्फ याद करने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट को समझकर ही तैयारी करें। सफलता पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके लिए 2018 में देश के 19 लॉ विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए होने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट-2018) की आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। राजधानी के हिंदौयतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रदेश के युवाओं को अवसर मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में आवेदन के लिए क्लैट की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यू.क्लैट.एसी.इन पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इस बार यह परीक्षा केरल के कोच्चि स्थित द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज द्वारा आयोजित की जा रही है।

क्लैट की उपयोगिता : इसके माध्यम से देश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में एलएलबी और एलएलएम की सीटों पर दाखिला लिया जाता है। क्लैट के लिए अँनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है, जबकि प्रवेश परीक्षा 13 मई को शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच होगी। क्लैट का आवेदन शुल्क अभ्यर्थी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए जमा करा सकेंगे। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों के लिए आवेदन शुल्क चार हजार रुपए और एससी/एसटी के लिए 3500 रुपए निर्धारित किया गया है।

आवेदन के लिए ये आवश्यक अहर्ताएं : एलएलबी ऑनलाइन में आवेदन के लिए 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 45 फीसदी अंक निर्धारित किया गया है। वहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 फीसदी अंक इंटर में निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा जो छात्र इस साल 12 वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वो भी इसमें अपीयरिंग के तौर पर आवेदन कर सकेंगे। वहाँ एलएलएम में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को एलएलबी या एलएलबी इंटीग्रेटेड या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग अभ्यर्थियों के परीक्षा में 55 फीसदी अंक और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के

अभ्यर्थियों के 50 फीसदी अंक होना अनिवार्य है। तभी वह फॉर्म भर सकेंगे।

परीक्षा में इस तरह के पूछे जाते हैं प्रश्न : क्लैट का पेपर दो घंटे का होता है। 2 घंटे के इस पेपर में 200 प्रश्न चार विषयों में पूछे जाते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स से दसवीं स्तर तक के गणित के सवाल रहते हैं। इसके लिए मैथ की निरंतर और नियमित प्रैक्टिस जरूरी होती है। इंग्लिश सेक्षन में ग्रामर से जुड़े सवाल होते हैं। साथ ही पैसेज भी आता है। जनरल नॉलेज में देश-विदेश की जुड़ी बड़ी घटनाओं पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। न्यायिक क्षेत्र से जुड़े केंट मुद्दों पर सवाल आते हैं। लीगल एप्टिट्यूड में लॉ से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें लॉ से जुड़े आपके नॉलेज को भांपा जाता है। साथ ही कुछ चर्चित मामलों से जुड़े सवाल आते हैं।

क्लैट में इस फॉर्मेट में होती है नेगेटिव मार्किंग : इसका प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम में आता है, जिसमें बहुवैकल्पिक 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। और नकारात्मक अंकन में 0.25 अंक काटे जाते हैं हर गलत उत्तर के लिए।

छात्रों को दी जा रहीं सुविधाओं के आधार पर तय होगी कॉलेजों की फीस

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की फीस अब विवि तय करेंगे। कॉलेज छात्रों को कौन-कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी आधारभूत संरचना कैसी है और स्तर कैसा है इसके आधार पर निजी कॉलेजों की फीस तय की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए एक केंद्रीय समिति भी बनाएगा जिसे विश्वविद्यालय अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की बैठक में यह तय हुआ।

अब तक विश्वविद्यालय कालेजों को संबद्धता देते हैं और फीस उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तय की जाती है। फीस निर्धारण में और पारदर्शिता लाने के लिए विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विवि अपने क्षेत्र के कालेजों की फीस का निर्धारण बेहतर तरीके से कर सकें। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर भी कमेटी बनाई जाएगी।

कालेजों की फीस तय होने के बाद इसे कार्यपरिषद की बैठक में भी रखा जाएगा और उच्च शिक्षा विभाग को भी रिपोर्ट दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कॉलेजों की फीस में एकरूपता संभव नहीं है लेकिन सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए इसके स्लैब बनाए जा सकते हैं।

एक प्लेटफार्म पर आएंगे सभी विश्वविद्यालय

बैठक में सभी विश्वविद्यालयों को एक प्लेटफार्म पर लाने के विषय पर भी चर्चा हुई। यह तय हुआ कि सभी विश्वविद्यालयों को आनलाइन एक इनरफेस पर लाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग इसे तैयार कराएगा। इसके तहत छात्र एक ही जगह से विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित हो रहे पाठ्यक्रम, फीस, फैकल्टी, छात्र संख्या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों को कैरियर गाइडेंस संबंधी जानकारी भी दी जाएगी।

स्मार्ट फोन पर उपलब्ध कराएंगे जानकारी

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग आईटी सेल के अधिकारियों ने बताया कि छात्रों को दिए गए स्मार्ट फोन पर भी एप उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी एक जगह से हासिल कर सकें।

रियल टाइम डाटा मिलेगा, कियोस्क जाने की जरूरत नहीं

बैठक में जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालयों को एक प्लेटफार्म पर लाने से रियल टाइम डाटा मिलेगा। छात्रों को कियोस्क जाने की जरूरत भी नहीं होगी। वे अपने मोबाइल से ही बैठे-बैठे विभिन्न विश्वविद्यालयों

की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों में होने वाले दाखिले भी इस प्रक्रिया में शामिल किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई कि रियल टाइम में यह जानकारी भी दी जा सकती है कि किस प्रोफेसर ने आज क्या पढ़ाया, कल वे क्या पढ़ाएंगे। इसके लिए प्रावधान करना होंगे और सभी को गंभीरता से प्रयास करना होंगे।

ई-प्रवेश प्लेटफार्म से दाखिले विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रवेश के लिए ई-प्रवेश प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा इसमें छात्र के आवेदन का वैरिफिकेशन, दस्तावेजों का सत्यापन आदि भी शामिल रहेगा। इसके माध्यम से विवि के यूटीडी में भी प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।

जिन्हें स्कालरशिप उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि अनेक ऐसे छात्र हैं जिन्हें स्कालरशिप मिलती है। लेकिन वे कालेज ही नहीं आते। वे कहीं नौकरी करते हैं। ओबीसी विभाग की स्कालरशिप में यह बात सामने आई है। इस कारण ऐसे छात्रों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का प्रावधान किया जाएगा। यह देखा जाना भी जरूरी है कि कालेज में पढ़ने आते भी हैं या नहीं। या केवल स्कालरशिप ही लेते हैं।

लाभ को आधार न बनाया जाए बैठक में बताया गया कि छात्रों को जो आनलाइन प्रवेश दिए जाते हैं उसका शुल्क लिया जाता है। इस पर अपर मुख्य सचिव बीआर नायडू ने कहा कि शुल्क को कम से कम किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार से लाभ को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। इस मौके पर अपर संचालक जगदीशचंद्र जटिया ने कहा कई विश्वविद्यालयों ने हाईकोर्ट को कई मामलों में जवाब नहीं दिया है। जवाब दाखिल किया जाए।

सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों का समाधान समय से करें। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना विश्वविद्यालयों और अनुदान प्राप्त कालेजों में लागू की जाएगी। बैठक में बरकतउल्ला विवि के कुलसचिव डा. यूएन शुक्ला, बुंदेलखंड विवि के डा. संजय तिवारी, डा. बी भारती, डा. एके पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

SWATI

Tuition Classes

Don't waste time Rush
Immediately for
Coming Session 2017-2018

Personalized
Tuition
up to
7th Class
for
All Subjects

Contact: Swati Tuition Classes
Sagar Premium Tower, D-Block, Flat No. 007
Mobile : 9425313620, 9425313619

भारत में कोरोना केसों में 43 फीसदी का उछाल

नई दिल्ली। ओमिक्रॉन (Omicron) के खौफ के बीच देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के गहरा गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि रोजाना अनेक बाले मामलों की संख्या में एक बार देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 961 फिर से तेजी दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में पहुंच गए हैं। यह मामले 22 राज्यों से रिपोर्ट हुए हैं। देशभर में 13,154 नए इष्टकूँड़ष्ट-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जो बुधवार की तुलना में 43 फीसदी अधिक है। कल देश में 9 हजार से कुछ ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए थे। वहीं, पिछले 24 घंटे में 268 मरीजों कोरोना के नए मामले बढ़ने से एक्टिव केस भी की संक्रमण के चलते मौत हुई है। अब तक कुल बढ़े हैं। फिलहाल, देश में 82,402 मरीजों का 4,80,860 मरीज जान गंवा चुके हैं। इस बीच, कोरोना का इलाज चल रहा है। यह कुल मामलों का

0.24 प्रतिशत है। मौजूदा समय में रिकवरी रेट 98.38% है। केंद्रीय स्वास्थ्य के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान 7,486 मरीज संक्रमण मुक्त यानी ठीक हुए हैं जबकि अब तक कुल 3,42,58,778 लोग संक्रमण से उभरने में कामयाब हो चुके हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.10 प्रतिशत है जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.76 प्रतिशत है। वैक्सीनेशन की बात करें तो पिछले 24 घंटे में लोगों को वैक्सीन की कांकड़ा 1,43,83,22,742 पहुंच गया है।

पवार ने की मोदी की तारीफ, कहा- मैंने यूपीए सरकार में उनके खिलाफ बदले की राजनीति का विदोध किया था

नई दिल्ली। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके की तारीफ करते हुए कहा कि उनका स्वभाव ऐसा है कि जब वह किसी काम को हाथ में लेते हैं, तो वह यह सुनिश्चित करते हैं कि काम अपने मुकाम तक पहुंच जाए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि वर्ष 2004 से 2014 के दौरान यूपीए के शासनकाल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदले की राजनीतिक करने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने उनके खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति का हमेशा विरोध किया, लेकिन यूपीए गठबंधन के कुछ लोगों ने गुजरात सरकार के कुछ लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। पुणे में बुधवार को एक कार्यक्रम में पवार ने कहा कि मेरे साथ तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह उस समय गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी तरह के बदले की कार्रवाई का विरोध किया था। पवार ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार में उनके अलावा ऐसा कोई नहीं था, जो उस समय मोदी से बात कर सकता था क्योंकि वह लगातार मनमोहन सरकार पर हमला बोलते रहे थे। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री थे। मोदी का वर्क स्टाइल की तारीफ कर बताया गया के काम करने के तरीके की तारीफ करते हुए पवार ने यह भी कहा कि वह एक बार कोई काम शुरू करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। पवार ने कहा, उनका स्वभाव ऐसा है कि एक बार जब वह किसी भी कार्य को हाथ में ले लेते हैं, तो वह यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि जब तक वह (कार्य) समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वह नहीं रुकेगे। प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ है और यही उनका मजबूत पक्ष है।

शरद पवार से सवाल किया गया कि ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी सीएम थे

और तत्कालीन सरकार के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे थीं, तब क्या आप और मनमोहन सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई न किए जाने के पक्ष में थे, इसके जबाब में पवार ने कहा कि यह आंशिक रूप से सत्य है। शरद पवार ने कहा, %जब मोदीजी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैं केंद्र में था। पीएम जब सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते थे, तब बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की अगुवाई मोदी करते थे और केंद्र पर हमलावर रहते थे। इसलिए ऐसी स्थिति में मोदी से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाती थी। यूपीए सरकार में मेरे अलावा एक भी ऐसा मंत्री नहीं था, जो मोदी से बात कर सके।

81 वर्षीय पवार ने कहा कि यूपीए की अंदरूनी बैठकों में वह सबको यही समझाते थे कि चाहे उनके और मोदी के बीच या बीजेपी के साथ कितने भी मतभेद हों लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह मुख्यमंत्री हैं। पवार ने कहा, मैं बैठकों में कहा करता था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और लोगों ने उन्हें चुना है। अगर वह यहां कुछ मुद्दों के साथ आ रहे हैं, तो वह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि मतभेदों को दूर किया जाए और उनके राज्यों के लोगों के हितों पर असर न हो।

शरद पवार ने यह भी कहा कि वह अकेले ऐसे मंत्री थे जो गुजरात जाकर वहां की समस्याओं को समझते थे। उन्होंने कहा, %मैं और मनमोहन सिंह यह राय रखते थे कि मोदी के खिलाफ बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम यह राय रखते थे कि हमें स्थापित कार्यशैली से बाहर जाकर कुछ नहीं करना चाहिए और हमने ऐसा कभी किया भी नहीं 1%

पीयूष जैन ने कोर्ट से की जब्त कैश वापस करने की मांग

कानपुर। उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने छापेमारी के दौरान जब्त किए गए अपने पैसों की मांग की है। कोर्टों द्वारा कैश के टैक्स घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए गानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने जब्त याजने की मांग के लिए



कोर्ट का दरवाजा खोखटाया है और उसने कोर्ट से टैक्स और जुर्माने की 52 करोड़ रुपए काटकर कर बाकी के बचे पैसे वापस करने की मांग की है। पीयूष जैन ने जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) से कहा है कि उसके परिसर से जब्त की गई बड़ी मात्रा में नकदी टैक्स और जुर्माना काटकर वापस कर दी जाए। जैन को कर घोटी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हियासत में जेज दिया गया है। डीजीजीआई के विशेष लोक अग्रियोजक यानी वकील अमरीश टंडन ने बुधवार को अदालत को सूचित किया कि पीयूष जैन ने कबूल किया है कि उसने टैक्स की घोटी की है और उसके ऊपर टैक्स घोटी और पैनली समेत 52 करोड़ रुपए का टैक्स बनाता है। वहीं, पीयूष जैन के वकील ने कोर्ट से कहा कि वह डीजीजीआई को निर्देश देकर पीयूष जैन पर बकाया 52 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में काट ले और शेष राशि वापस कर दें। हालांकि, इसके जवाब में डीजीजीआई के वकील अमरीश टंडन ने कहा कि पीयूष जैन के घरों से जो पैसा बरामद हुए हैं, वे टैक्स घोटी के हैं, इसलिए वापस नहीं किया जाएगा। विशेष लोक अग्रियोजक टंडन आगे कहा कि अगर पीयूष जैन अतिरिक्त 52 करोड़ रुपए जुर्माना देना चाहते हैं, तो डीजीजीआई इसे स्वीकार करेगा। टंडन ने कोर्ट को बताया कि कानपुर में पीयूष जैन के आवास से बरामद 177 करोड़ रुपए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में जमा कर दिए गए हैं और यह भारत सरकार के पास रहेगा। इतिहास में सबसे बड़ी बरामदी में से एक इस कांड में डीजीजीआई ने कानपुर और कबूज में पीयूष जैन से जुड़े कई परिसरों में छापे के दौरान 196 करोड़ रुपए से अधिक नकद, 23 किलोग्राम सोना और 6 करोड़ रुपए का घंटन का तेल जब्त किया।

ओबीसी आरक्षण पर मग्न में हंगामा- भीम आर्मी लीडर चंद्रशेखर समेत एक हजार से ज्यादा लोग हियासत में, राजनेता भी सक्रिय

भोपाल। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवास घेरने की राजनीति के दौरान रविवार को हंगामा हो गया। ओबीसी महासभा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे करीब एक हजार लोगों को पुलिस ने हियासत में लिया है। एयरपोर्ट से गांधी नगर पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर को भी पकड़ा गया है। दरअसल भोपाल में रविवार को आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने सीएम हाउस घेराव की चेतावनी दी थी। इसी के तहत प्रदर्शन हो रहा है। रविवार सुबह कई संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने भी तैयारियां कर रखी थीं। खजूरी सड़क थाना और परवलिया सड़क थाने से भोपाल आने वाले रासे सील कर दिए गए हैं। सीहोर से भोपाल आ रहे लोगों को खजूरी सड़क थाने में रोक लिया गया। ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और सीहोर जिले की ओर वापस भेज दिया गया। रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद रोड पर रोककर कार्यकर्ताओं को थाने में बैठाया जा रहा है।

नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप : मामले में बढ़ता हंगामा देख राजनेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ओबीसी महासभा द्वारा पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण प्रदान करने की मांग को लेकर आज भोपाल में प्रदर्शन की पूर्व से ही घोषणा की गई थी, लेकिन पता नहीं शिवराज सरकार को ओबीसी वर्ग से परहेज़ क्यों, सरकार उनके दमन पर क्यों उतारू हो गई है। भाजपा और उससे जुड़े संगठन को तमाम आयोजनों की छूट.. लेकिन ओबीसी वर्ग के आयोजन पर रोका गया और अब उन्हें हियासत में लिया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है। आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है। उनके साथ मारपीट की जा रही है और यह सब खुद को इस वर्ग की हितैषी बताने

वाली सरकार में हो रहा है? ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग का कितना भी दमन कर लो, यह वर्ग अपने हक की मांग को लेकर संघर्ष करता रहेगा। यह डरने-दबने वाला नहीं है, कांग्रेस इन वर्गों के साथ खड़ी है और इनके हित, उत्थान व कल्याण के लिए हम सदैव संकल्पित हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया- भूपेंद्र सिंह : ओबीसी महासभा के आंदोलन को लेकर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ओबीसी को लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं। दूसरे संगठनों को जोड़कर प्रदेश का वातावरण खराब करना यह कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिले इसके लिए प्रदेश सरकार ने देश के बड़े वकील हरीश सालवे को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया है जिस पर कल सुनवाई है। केंद्र सरकार भी अभिभावक के रूप में सुप्रीम कोर्ट में बात रखेगी कि मध्य प्रदेश सरकार को 4 महीने का समय मिले जिससे ओबीसी वर्ग की अर्थिक सामाजिक की स्थिति की गणना की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी पंचायत में आरक्षण मिले, सरकार ने कैबिनेट से ऑर्डर्सेस वापस लिया।

शिवराज सरकार ने बर्बरता का परिचय दिया: कमलेश्वर पटेल : ओबीसी महासभा के आंदोलन को कुचलने के मामले को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और अनुस

चका वक सारा अली खान ने जीता दिल, धनुष और अक्षय कुमार का भी चला जादू, हटकर है ये लव स्टोरी



'अतरंगी रे' की कहानी रिंकू सूर्यवंशी (सारा अली खान) और विष्णु (धनुष) के आस पास घूमती है, जिनकी जबरदस्ती शादी हुई है। विष्णु के होम टाउन जाते वक दोनों इस बात पर सहमति जता लेते हैं कि वे दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वहीं विष्णु की अगले दो दिनों में शादी है। अब फिल्म में एंट्री होती है सज्जाद अली की, जो किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं और जिसे रिंकू से प्यार है। अब रिंकू को सज्जाद से भी प्यार है और वो विष्णु की भी पसंद करती हैं और कैसे इन सिचुएशन से वो डील करती है, यही है अतरंगी की कहानी, हालांकि फिल्म देखने पर आपको महसूस होगा कि ये कोई आम लव स्टोरी नहीं है।

क्या कुछ है खास- अतरंगी रे का स्क्रीनप्ले काफी शानदार है, वहीं फिल्म का म्यूजिक भी आपको बांधे रखता है। हिमांशु शर्मा का लेखन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, जहां प्यार की परिभाषा कुछ और ही है। फिल्म के सीन्स को इतनी बारिकी से फिल्माया गया है कि आप मुस्कुराएंगे भी और साथ ही साथ रोएंगे भी। अतरंगी रे की लव स्टोरी आपको बाकी बॉलीवुड फिल्मों से काफी अलग महसूस होगी। फिल्म में सारा अली खान ने दिल जीतने वाला काम किया है, उनके एकसेट से लेकर हाव भाव तक, सब कुछ एक दम %चका चक% है। वहीं अक्षय और धनुष का भी काम बढ़िया है, लेकिन सारा के आगे फीके लगे हैं। देखें या नहीं- इस फिल्म को आप देख सकते हैं। सारा अली खान की बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ ही इस फिल्म की लव स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आनंद एल राय ने अपना जादू चला दिया। फिल्म का एक हिस्सा मेंटल हेल्थ के मुद्दे पर भी बात करता दिखता है।

सलमान खान का ऑटो चलाते हुए वीडियो वायरल, फैन बोले- भाई के शौक भी अजीब हैं

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में अपनी आलीशान रेंज रोवर कार छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाते नजर आए। दबंग खान का ये वीडियो उनके पनवेल वाले फॉर्महाइस के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में सलमान खान सिर पर कैप लगाए और शॉर्ट्स-टीशर्ट पहने ऑटो रिक्शा चलाते नजर आ रहे हैं। सलमान खान का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है और फैन पेजों पर इसे जमकर शेयर किया जा रहा है। ऑटो चलाते नजर आए सलमान खान : इस वीडियो में सलमान खान के ऑटो ड्राइव करने से पहले उनके ऑटो में पीछे कुछ लोग बैठते भी हैं जिन्हें ड्राइव करके दबंग खान ले जा रहे हैं। मालूम हो कि सलमान खान आमतौर पर अपनी रेंज रोवर कार से ही घूमने निकलते हैं। वो गाड़ी चलाने की बजाए आमतौर पर को-ड्राइवर सीट पर या फिर पैसेंजर सीट पर ही बैठना पसंद करते हैं। वीडियो पर ऐसा था फैंस का रिएक्शन : बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के इस वीडियो पर फैंस का रिएक्शन भी देखने लायक था। एक यूजर ने लिखा- भाई के शौक भी अजीब हैं। वहीं एक ट्रोल ने लिखा- और कुछ कसर रह गई हो तो वो भी पूरी कर लो। वया काटून लोग हैं यार। एक फैन ने दबंग खान के सपोर्ट में लिखा- आप ग्रेट हो सर इसीलिए सबसे अलग हो। एक अन्य फैन ने लिखा- वाह सर, ये हुई ना बात।

